International Journal of Research inSocial Science
Vol. 12 Issue 03, March 2022,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

कौशल विकास के लिए उच्च शिक्षा

डॉ0 केशरी नन्दन मिश्रा

एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास), हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय पी.जी. कालेज, नैनी, इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश, भारत।

नई तकनीकों, नए प्रकार की नौकरियों, बदलती कौशल आवश्यकताओं ने कौशल प्रशिक्षण पर बहुत जोर दिया है। अधिक से अधिक नौकरियों में महत्वपूर्ण सोच, संचार, सहयोग और रचनात्मकता जैसे कौशल अब महत्वपूर्ण हैं। कौशल प्रशिक्षण आजीवन सीखने की प्रक्रिया बन गया है। वर्तमान परिदृश्य को देखने पर पता चलता है कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो रहा है। टेक ऑफ पॉइंट पर उन्नत देशों में मानव शक्ति है जो पहले से ही अनुभवी हैं। नया ज्ञान अब हमारे देश में युवाओं के लिए सुलभ है लेकिन यह ज्ञान उन्नत देशों के लिए काफी लंबे समय से उपलब्ध है। युवा भारतीयों को शायद उनके प्लस बिसवां दशा या शुरुआती तीसवां दशक में जिम्मेदारियों को संभालने के लिए बुलाया जाएगा, जबकि उन्नत और विकसित देशों में ऐसा करने के लिए वृद्ध लोग होंगे, "2020 तक भारतीय आबादी की औसत आयु 40 वर्ष की तुलना में 29 वर्ष होगी। यूएसए, यूरोप में 46 साल और जापान में 47 साल।" (रोजगार समाचार, 2-8 सितंबर, 2018)। एक लाभ के रूप में यह हमारे देश में उच्च शिक्षा के लिए एक चुनौती है, कौशल विकास और उच्च शिक्षा के एकीकरण की मांग करता है।

भारत में युवाओं की सबसे बड़ी संख्या (14 से 25 आयु वर्ग) और उच्चतम वैश्विक बेरोजगारी दर है - ये हमारी शिक्षा प्रणाली की प्रकृति और दक्षता के संकेतक हैं। इसके विपरीत, विशिष्ट कौशल द्वारा रोजगार बाजार को तेजी से पुनर्परिभाषित किया जा रहा है। बीस साल पहले जिस तरह से लोग करते थे, कोई भी व्यवसाय और कंपनियां नहीं चलाता है। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाली कंपनी में काम करने के लिए आवश्यक संपूर्ण कौशल में बदलाव आया है और शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा, नई वास्तविकताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती है।

भारत की प्रशिक्षण क्षमता सीमित है। आधिकारिक तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि हर साल लगभग 50 लाख युवा कार्यबल में प्रवेश करते हैं। इसके विपरीत भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीटी) की ज्ञात वर्तमान क्षमता, जो अभी भी भारत की व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की रीढ़ है, प्रति वर्ष केवल 25 लाख है। इसलिए भारत में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की क्षमता और पैमाने को बढ़ाना समय की मांग है। प्रशिक्षण उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए और उद्योग की आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। साथ ही, प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार योग्यता के मुद्दे पर भी उचित बल देने की आवश्यकता है। इसके लिए उद्योग के साथ संबंध स्थापित करना और शिक्षुता कार्यक्रमों को लागू करना आवश्यक है। भारत के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को न केवल युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए विपणन योग्य कौशल से

लैस करना चाहिए बल्कि युवाओं को स्वरोजगार करने या उद्यमिता अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। भारत में अभी तक स्नातक उद्योगों द्वारा नियोजित होने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं। यह शिक्षा के दौरान अपर्याप्त इनपुट का परिणाम है, जिससे आवश्यक क्षमता और कौशल के बीच अंतर पैदा होता है।

कौशल विकास एक अतिरिक्त पाठ्यक्रम नहीं है जिसे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसे ऐसे युवाओं के प्रशिक्षण और शिक्षा में एकीकृत करने की आवश्यकता है, जिन्हें देश के उद्योग को चलाने वाले तंत्र का हिस्सा बनने के लिए आसानी से रोजगार योग्य और सक्षम होना होगा। . इस स्थिति में नेशनल सिल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) पर एक नज़र डालना उपयोगी है। एनएसक्यूएफ प्रत्येक योग्यता आधारित व्यावसायिक कौशल के लिए स्तरों और क्रेडिट को परिभाषित करता है। यह एक क्रेडिट ट्रांसफर फ्रेमवर्क स्थापित करता है जो औपचारिक और व्यावसायिक शिक्षा के बीच मार्ग बनाने की अनुमति देता है। भारत में NSQF को 27 दिसंबर, 2013 को अधिसूचित किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी NVEQF (राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक योग्यता फ्रेमवर्क) सहित अन्य सभी रूपरेखाएँ NSQF द्वारा अधिक्रमित हैं। एनएसक्यूएफ के तहत, शिक्षार्थी औपचारिक, गैर-औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से किसी भी स्तर पर आवश्यक योग्यता के लिए प्रमाणन प्राप्त कर सकता है। यह एक गुणवत्ता आश्वासन ढांचा है।

इस संबंध में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में औपचारिक शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने के लिए भारत में शुरू की गई कुछ योजनाओं का संक्षेप में उल्लेख करना सार्थक है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

1. सामुदायिक कॉलेज:

एक सामुदायिक कॉलेज भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के तहत एक संस्था है जिसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों के छात्रों को नौकरी उन्मुख शिक्षा प्रदान करना है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो विभिन्न कौशल उन्मुख के साथ-साथ पारंपरिक पाठ्यक्रमों के साथ माध्यमिक स्तर से ऊपर और डिग्री स्तर से नीचे की शिक्षा प्रदान करती है। इन कॉलेजों में 12वीं कक्षा के बाद प्रवेश मिल सकता है और कोई आयु मानदंड नहीं है। इन पाठ्यक्रमों की अवधि 6 महीने से 2 वर्ष तक है। सामुदायिक कॉलेज की अवधारणा मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से उत्पन्न हुई है जहां ऐसे संस्थान लगभग सौ वर्षों से अस्तित्व में हैं। यहीं से सामुदायिक कॉलेजों को प्रमुखता मिली और भारत सहित दुनिया भर के विभिन्न देशों में स्थापित हुए। वर्तमान में भारत में लगभग 150 सामुदायिक कॉलेज हैं जिन्हें यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है। यहां सूचना प्रौद्योगिकी, फैशन डिजाइन, सौंदर्य और कल्याण, होटल प्रबंधन, हेल्थकेयर इत्यादि जैसे विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम पेश किए जाते हैं। यहां शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता किए बिना सस्ती कीमत पर पाठ्यक्रम पेश किए जाते हैं। इससे शिक्षार्थियों को सीधे रोजगार क्षेत्र या आगे की शिक्षा में जाने का अवसर मिलता है।

2. व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक (बी.वोक।):

व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक (बी। वोक।) उन छात्रों के लिए कई क्षेत्रों में उपलब्ध हैं जिन्होंने अपनी 12 वीं कक्षा पूरी कर ली है। यह मुख्य रूप से उन युवाओं के लिए लक्षित है जो सीखने, कमाने और बढ़ने के लिए अपने रोजगार के अवसरों को बढ़ाना चाहते हैं। इन पाठ्यक्रमों का लाभ यह है कि इंजीनियरिंग या बीकॉम या

बीएससी जैसे डिग्री पाठ्यक्रमों के मुकाबले, कई निकास बिंदु हैं और उद्योग के लिए निरंतर जोखिम है। पारंपरिक यूजी पाठ्यक्रमों के विपरीत, B.Voc. राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSFQ) के अनुसार पाठ्यक्रम को अक्सर नौकरी की भूमिका के विवरण के साथ मैप किया जाता है। पाठ्यक्रम उद्योग और कार्य एकीकृत है और यदि किसी कारण से कोई व्यक्ति तीन साल का कार्यक्रम पूरा करने में असमर्थ है, तो भी वह क्रमशः प्रथम और द्वितीय वर्ष पूरा करने के बाद डिप्लोमा या उन्नत डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है। B.Voc कोर्स देश भर के 200 से अधिक कॉलेजों में पेश किया जाता है। इसमें डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और बैचलर का तीन साल का कोर्स है। पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम में 40% सामान्य शिक्षा (सिद्धांत) और 60% व्यावसायिक प्रशिक्षण (व्यावहारिक) घटक हैं। सेमेस्टर प्रणाली का पालन किया जाता है और पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद क्रेडिट की पेशकश की जाती है। पाठ्यक्रमों से एनएसएफक्यू का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिन छात्रों ने बी. वोक पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है, वे व्यावहारिक फोकस की सराहना करते हैं और आश्वस्त हैं कि उनके लिए उपयुक्त नौकरी पाने की संभावना अन्य स्नातकों की तुलना में अधिक है। कोई व्यक्ति क्रमशः प्रथम और द्वितीय वर्ष पूरा करने के बाद डिप्लोमा या उन्नत डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है, जो यह दर्शाता है कि ज्ञान और कौशल को हर स्तर पर महत्व दिया जाता है और एक व्यक्ति बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त नौकरी के लिए योग्य है। कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में उद्यमी बनने की संभावनाएं तलाश सकता है।

3. दीन दयाल उपाध्याय कौशल केंद्र (डीडीयू-केके):

यूजीसी ने बारहवीं योजना अवधि के दौरान ज्ञान प्राप्ति और कुशल मानव क्षमताओं और आजीविका (कौशल) के उन्नयन के लिए 100 दीन दयाल उपाध्याय कौशल केंद्र (डीडीयू-केके) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। ये केंद्र डिप्लोमा और बी.वोक से परे व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करेंगे। डिग्री। केंद्र न केवल कौशल पर ध्यान केंद्रित करेंगे बल्कि उद्यमिता के लक्षण विकसित करने पर भी ध्यान देंगे। केंद्र डिप्लोमा, उन्नत डिप्लोमा, बी.वोक के संबंध में छात्र नामांकन की एक पैरामेडिकल संरचना को बनाए रखने का प्रयास कर सकता है। और पीजी और अनुसंधान स्तर पर आगे की पढ़ाई। ये केंद्र विशेष क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में काम करने के लिए देश की उच्च शिक्षा प्रणाली और उद्योग के बीच समन्वय स्थापित करेंगे। पाठ्यक्रमों की योजना/डिजाइन इस प्रकार तैयार की जाएगी कि अनुसंधान डिग्री स्तर तक के विभिन्न स्तरों पर एकाधिक प्रवेश और निकास का प्रावधान हो। इनमें सामुदायिक कॉलेज योजना और बी.वोक के तहत पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रम भी शामिल होंगे। यूजीसी की डिग्री प्रोग्राम योजना के अनुसार, सभी विश्वविद्यालय जो यूजीसी से सामान्य विकास सहायता प्राप्त करते हैं और एनएएसी या राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हैं या मान्यता के लिए आवेदन किया है, उन सभी विश्वविद्यालयों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पेशकश की सहायता के लिए विचार किया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ सहयोग किया जाएगा।

4. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी):

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) की स्थापना 2009 में विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति प्रदान करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई थी। यह व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों को बनाने और

वित्त पोषित करने और कौशल विकास के लिए समर्थन प्रणाली स्थापित करने के लिए एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर गठित किया गया था। एकीकृत कौशल विकास बुनियादी ढांचे के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक योग्यता फ्रेमवर्क (NVEQF) का गठन किया जाएगा। यह ढांचा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणालियों की संबद्धता और मान्यता के लिए है। कौशल विकास प्रदान करने से प्राप्तकर्ता न केवल उद्योग की मांगों को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करना चाहिए। रोजगार योग्यता के लिए कौशल विकास की आवश्यकता कार्यबल के प्रत्येक वर्ग में है। इसे सीढ़ी के सबसे निचले पायदान से लेकर सबसे ऊंचे पायदान तक सराहा जाना चाहिए। उद्योग में कौशल विकास अपरिहार्य है।

निष्कर्ष

शिक्षा की प्रक्रिया केवल पुस्तकों को पचाना नहीं है। यह कई सह-पाठयक्रम गतिविधियों को करने के बारे में भी है जो सामान्य रूप से जीवन और विशेष रूप से शिक्षा को व्यापक अर्थ देते हैं। भारत में इस तरह के समग्र विकास के अवसर पर्याप्त नहीं हैं। उसी के लिए सुविधाओं की कमी है या भारत में आसानी से उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि जहां सुविधाएं मौजूद हैं, वहां इसकी जानकारी का अभाव है। समुदाय आधारित कार्यक्रम होने चाहिए और सामाजिक मुद्दों पर काम करना चाहिए। सामुदायिक जुड़ाव का तात्पर्य साझेदारी और पारस्परिकता के संदर्भ में ज्ञान और संसाधनों के पारस्परिक रूप से लाभकारी आदान-प्रदान के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों और उनके बड़े समुदायों के बीच सहयोग से है। जब छात्र समुदाय के लोगों की जीवन स्थितियों से परिचित हो जाते हैं तो संचार कौशल, समस्या समाधान, संवादात्मक कौशल, नागरिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। साथ ही, यह प्लेसमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करा सकता है। आदर्श रूप से, अपनी शिक्षा पूरी करने वाले युवाओं को नौकरी की तलाश नहीं करनी चाहिए, वास्तव में, नियोक्ताओं को विश्वविद्यालय के दरवाजे पर आना चाहिए और इन कुशल युवाओं की तलाश करनी चाहिए।

References

- Aggarwal, J. (2009). *Recent Developments and Trends in Education* (third edition). Delhi : Shipra Publications.
- Aikara, J. (2004). *Education - Sociological Perspective.* Jaipur: Rawat Publications.
- Krishnan, K.P. & Nambiar, D. (2017, September 2-8). Skill India: Challenges, Achievements and the Way Forward, *Employment News* (2018, Aug. 3).